3 दिसम्बर को पूसा, बिहार में डाक्टर राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह के दौरान माननीय केन्द्रीय कृषि एवं कृषि किसान कल्याण मंत्री के द्वारा दिया जाने वाला भाषण

मुझे बिहार की पावन धरा और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीजारोपण की भूमि पर यहां आप सब के बीच आकर अत्यधिक प्रशन्नता हो रही है।

मेरे लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि आज इस महान विश्वविद्यालय जिसका नाम इस धरती के महान सुपुत्र भारत रत्न डाक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखा गया है, उसका स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। मुझे आप को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि संयोगवश इस विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी डाक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस पर ही पड़ रहा है, जिनके नाम पर इस केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। दूसरा अद्भुत संयोग यह है कि डाक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस जो कि 3 दिसम्बर को आता है, इस पावन तिथि को भी पूरे देश में कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है और आज सारा देश हमारे प्रथम कृषि मंत्री के सम्मान में इस दिन को माना रहा है।

डाक्टर राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का इतिहास ब्रिटिश शासन के दौरान से शुरु होता है। जिस पावन भूमि पर यह विश्वविद्यालय स्थित है वह खेती के लिए पूरे देश में सर्वाधिक योग्य स्थान है क्योंकि इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए जल और पशुओं के लिए चारा मौजूद था। बाद के वर्षों में यहाँ फसल उत्पादन से संबन्धित नीति को अपनाने के साथ-साथ कृषि अनुसंधान कार्य को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ 1905 में कृषि अनुसंधान संस्थान कि स्थापना की गई थी। 1918 में इस संस्थान का नाम बदलकर इम्पीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। भारत और इंग्लैंड के उच्च स्तरीय कृषि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद पूसा कृषि संस्थान को देश के कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया गया। सन 1934 में बिहार में जबरदस्त भूकंप आने के कारण व्यापक पैमाने पर तबाही और विध्वंस का सामना करने के कारण इस कृषि अनुसंधान संस्थान को नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां स्थान का आज भी पूसा नाम से जाना जाता है।

कृषि के क्षेत्र में क्रांति आने के बाद सम्पूर्ण विश्व का मशहूर वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ताओं के सफल नेतृत्व में इस इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में

गेहूं, चावल, लाल मिर्च, तंबाकू, अल्सी, सरसों, दलहन, सब्जियों और काश्तकारों तथा किसानों दोनों के लिए लाभकारी अन्य फसलें से खाद्य निर्माण, पादप की जल संबन्धित आवश्यकता पर अनुसंधान कार्य आज तक उत्कृष्ट श्रेणी में शामिल रहे है। इसके महत्वपूर्ण योगदानों में से एक यह है कि इसके द्वारा पशुओं की विशुदत: देसी साहीवाल नस्ल में उल्लेखनीय सुधार किया गया है।

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अनेक उल्लेखनीय सफलताऐं हासिल की गई हैं। जिन्हें प्रदेश की कृषि के प्रगति में मील का पत्थर कहा जा सकता है। इनमें खेत की उत्पादकता तथा खेत से होने वाली आय में वृद्धि, संस्थान निर्माण, मानव संसाधन, नई तकनीकों का विकास, कृषि का विविधीकरण, नये अवसर पैदा करना तथा जानकारी के नये श्रोतों का विकास करना शामिल है। कृषि में नवीन तकनीकों के तालमेल से उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर देश के विकास में विश्वविद्यालय ने अपनी भूमिका का हमेशा निर्वहन किया है। जो सराहनीय है।

कृषि में शिक्षा का महत्व

मानव संसाधन एक देश की सबसे महत्वपूर्ण संपदा मानी जाती है। वर्तमान केंद्र सरकार का उदेश्य एक कुशल मानव संसाधन का निर्माण करते हुए कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के विकास को उनके उच्चतम स्तर पर लाकर देश के किसानों को लाभान्वित करना है। समय के साथ-साथ भारतीय कृषि शिक्षा प्रणाली में कई उपायों की ज़रूरत महसूस की गई। कृषि विज्ञान और शिक्षा के प्रति युवकों की उदासीनता से कृषि संकाय में उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की कमी हुई है। मेड-इन-इंडिया, स्टार्ट-उप-इंडिया, कौशल-भारत आदि परियोजनाओं पर ज़ोर दिए जाने के साथ-साथ कृषि शिक्षा प्रणाली में सुधार किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि कृषि संकाय से निकलने वाले छात्रों को यथोचित रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ ही कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की बदलती हुई आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके।

नई पहल

- हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विशेष पहल से 25 जुलाई 2015 को पटना में स्टूडेंट रेडी (ग्रामीण उद्यम, जागरूकता और विकास योजना) शुरु की गई,
- इसके तहत केंद्र सरकार कृषि विज्ञान के स्नातक छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के आखिरी साल (चौथे साल में) 6 महीने की अवधि के लिए प्रतिमाह 3 हजार रूपये(पूर्व में 1000 रू) की छात्रव्रति देगी। इस कार्यक्रम से प्रयोगिक ज्ञान अर्जन कार्यक्रम (ईएलपी) और ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (आरएडब्लूई) तथा औद्योगिक संबंध इसके घटकों के रूप में शामिल होंगे। स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम का उदेश्य यह है कि कृषि स्नातकों को रोजगार अवसरों को सुनिश्चित करने और आधुनिक ज्ञान से सुसज्जित कृषि उद्यम को विकसित करने के लिए तैयार किया जाए।
- स्टूडेंट रेडी का पाठ्यक्रम कृषि स्नातकों को स्नातक डिग्री प्राप्त करने में एक आवश्यक घटक के रूप में रखा गया है, ताकि इस क्षेत्र में तजुर्बाकार और व्यावहारिक प्रशिक्षण लिए हुए लोग फील्ड में आए।
- कृषि एवं संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में डिग्री को पेशेवर डिग्री(professional) के रूप में घोषित किया गया
- राष्ट्रीय प्रतिभा स्कॉलर्शिप-यू. जी को रु 1000 से बढ़ा कर 2000 किया गया
- राष्ट्रीय प्रतिभा स्कॉलर्शिप-पी.जी के लिए रु 3000 की घोषणा की गई

विश्व बैंक के सहयोग से देश में कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 1,000 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परियोजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का उद्येश्य उत्कृष्टता के नये केन्द्रों की स्थापना करना, पिछड़े राज्यों में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष बल देना, प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क स्थापित करना तथा कृषि विश्वविद्यालय के प्रत्यायन एवं पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाकर गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना है।

भारत विश्व के उन देशों में से एक है जहां कृषि अनुसंधान की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 30 हजार वैज्ञानिक, 1 लाख से भी अधिक सहायक कार्मिक कृषि अध्यापन और अनुसंधान कार्य में सक्रिय हैं। इस समय हमारे देश में 73 कृषि विश्वविद्यालय और 100 से भी अधिक आईसीएआर अनुसंधान संस्थान हैं जो कृषि समुदाय की जरूरतों के हिसाब से काम कर हैं। हमारे अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सृजित कृषि प्रौद्योगिकीयों के कारण हम राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्म निर्भर हो गए हैं, और आज हम कई खाद्यान्नों के प्रमुख उत्पादक हैं। हाल ही के वर्षो में हमारा अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 260 मिलियन टन से भी अधिक हो गया है। बागवानी उत्पादन लगभग 283 मिलियन टन , दूध का उत्पादन 146 मिलियन टन, अंडे 78.5 बिलियन और मछली का उत्पादन 10.16 मिलियन टन से भी अधिक रहा है। बावजूद इसके वास्तविक उत्पादन क्षमता से हम काफी दूर है। मुझे विश्वास है कि नए विकास क्रम और प्रौद्योगिकियों के आने से हमारे खेतों का उत्पादन हमारे बढ़ती हुई खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

अब तक देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के साथ- साथ दो और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फ़ाल में और दूसरा बुंदेलखंड क्षेत्र में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी है। वर्तमान भारत सरकार कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबंध है, क्योंकि हमारे देश में कृषि की प्रगति और विकास मुख्य रूप से हमारे उच्च कृषि शिक्षा संस्थान और अनुसंधान संस्थानों पर निर्भर करता है। सरकार ने इस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए है, जिसमें कुछ और नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापित करना, इन उठाए गए कदमों मे से एक है।

भारतीय कृषि अनुसंधान भवन देश में उच्च स्तरीय कृषि शिक्षा के क्षेत्र में आयोजन, विकास, समन्वय और गुणवत्ता आश्वासन की देशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। आईसीएआर शैक्षणिक सुविधायों, अवसंरचना और संकायगत सुधारों के आधुनिकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कृषि विश्वविद्यालय को नियमित रूप से वित्तीय और व्यावसायिक सहायता (विकास अनुसंधान) उपलब्ध करता है। आईसीएआर मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय एकीकरण और अंतरप्रजनन न्यूनीकरण के निमित कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष पीएचडी छात्रों को आकर्षित करने के प्रयोजनार्थ स्नातक पूर्व छात्रों, छात्रवृत्ति अनुसंधान स्कालरों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृति जैसे कई वजीफे देता है।

आईसीएआर ने नवीन और आविभ्रवित आधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालयों को सुरक्षित एवं सुदृढ़ करने के लिए उत्कृष्टता क्षेत्र स्कीम शुरू की है। इसके द्वारा

स्नातक पूर्व स्तर पर छात्रों को कौशल उन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिए सभी 434 प्रायोगिक ज्ञानार्जन माडयूलों की भी स्थापना की गई है। अध्यापकों और वैज्ञानिकों को क्षमता निर्माण करने के लिए आईसीएआर आधुनिक और आविर्भावित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्य संचलित करने के लिए भी सहायता देता है।

सन 1905 में स्थापित इस संस्थान के बावत शिक्षा सलाहकारों का उतकृष्टता क्षेत्र बनाने का सपना साकार हो गया है, और पूसा कृषि संस्थान एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो चुका है। मुझे आशा है कि यह विश्वविद्यालय भविष्य में कृषिगत क्रियाकलापों का एक मुख्य केन्द्र बन जाएगा। इस क्षेत्र में कृषिगत विकास से सर्वमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होने के साथ कृषि को भी एक सशक्त आधार प्राप्त होगा जिसके फलस्वरूप एक ज्ञान संपन्न एवं खुशहाल कृषक समुदाय का अभूद्य होग।

मैं यहां पर उपस्थित सभी महानुभावों से इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहुँगा कि बदलती परिस्थितियों, बदले हुए हालात में हमारे मंत्रालय का नाम भी परिवर्तित कर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया है। अब हमें इसी उद्देश्य पर तत्परता से काम करना है, ताकि किसानों के चेहरे पर मुस्कान वापस लायी जा सके।

मंगल में जीवन की खोज अच्छी है, लेकिन और ज्यादा अच्छा है – जीवन में मंगल की खोज करना। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सब को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाऐं।

डॉ राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का इतिहास

1 अप्रैल, 1905	:	पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई
1918	:	संस्थान का नाम बदलकर इम्पीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया
जनवरी, 1934	:	महाविनाशकारी भूकंप पूरे बिहार प्रदेश में आया, परिणाम स्वरूप संस्थान को काफी नुकसान हुआ
1935	:	इम्पीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान को नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया
3 दिसम्बर, 1970	:	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पूसा में की गई
6 मार्च, 2009	:	योजना आयोग ने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया, किन्तु 2014 तक राज्य सरकार एवं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के बीच सहमति नहीं बन पायी, विवाद चलते रहे।
25 सितंबर, 2012	:	कृषि मंत्रालय द्वारा ड्राफ्ट समझौता पत्र बिहार सरकार को भेजा गया
25 जनवरी, 2015	:	समझौता पत्र पर केन्द्रीय कृषि मंत्रालय एवं बिहार सरकार ने हस्ताक्षर किए
मई, 2016	:	भारतीय संसद ने डाक्टर राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का एक्ट पास कर दिया जो कि 7 अक्तूबर, 2016 से लागू कर दिया गया है